मुख्य न्यायाधीश एच.एन. सेठ और न्यायमूर्ति एम.एस. लिब्रहान के समक्ष,

क्रांति कुमार चोपड़ा-आवेदक

बनाम

भारत सरकार और अन्य-प्रतिवादी

सिविल विविध 1986 की सिविल रिट याचिका संख्या 1491, 1979 की 738

5 जून 1987

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-परिसीमा अधिनियम (XXXVI, 1963)-धारा 5-न्यायालय रिट कार्यवाही में पारित आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन को गुण-दोष के आधार पर और देर से खारिज कर रहा है-जहां ऐसा आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है- उच्च न्यायालय - क्या समीक्षा आवेदन प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने के लिए किसी आवेदन पर निर्णय लेने के लिए बाद की कार्यवाही में अधिकार क्षेत्र है।

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि कि समीक्षा आवेदन इस न्यायालय द्वारा दो कारणों से खारिज कर दिया गया था :

(1) आवेदन समय से बाधित था और

(2) गुण-दोष के आधार पर पहले के आदेश की समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। यदि उक्त आवेदन, उसे प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने के लिए आवेदन के अभाव में, केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह समय से बाधित था, तो आवेदक के लिए कुछ व्यवहार्यता के साथ आग्रह करना संभव हो सकता था कि जैसा कि न्यायालय ने उचित स्पष्टीकरण के अभाव में इस आधार पर समीक्षा आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि इसमें देरी हुई थी, वह अब भी उस पर विचार कर सकता है यदि उसे अब पेश की जा रही देरी के लिए स्पष्टीकरण उपयुक्त लगता है। लेकिन जहां समीक्षा आवेदन को न केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि यह समय से बाधित था, बल्कि इस आधार पर भी खारिज कर दिया

गया है कि योग्यता के आधार पर भी समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। हमारी राय में इसे प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने के अनुरोध पर केवल विचार करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यहां तक कि अगर आवेदक द्वारा पेश किया गया स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया जाता है, तो भी इस न्यायालय के लिए उसके द्वारा पहले निकाले गए निष्कर्ष को खारिज करना संभव नहीं होगा, अर्थात्, योग्यता के आधार पर आदेश की समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। यह न्यायालय गुण-दोष के आधार पर समीक्षा आवेदन को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इसके विपरीत रुख नहीं अपना सकता है क्योंकि उस आदेश के संबंध में उसके पास न तो अपीलीय और न ही पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है, जो अभी भी कायम है। इसलिए, यह मानना होगा कि समीक्षा आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने के अनुरोध पर विचार करना व्यर्थ होगा।

(पैरा 12 और 13)

151 सी.पी.सी. के साथ पठित धारा 5 सीमा अधिनियम के तहत देरी की माफी के लिए आवेदन। सिविल रिट याचिका संख्या 738-79 में समीक्षा आवेदन 73-83 में जैसा कि भारत के माननीय एस.सी. द्वारा एस.एल.पी. में देखा गया है। 1984 के 10142 ने 3 मार्च, 1986 को निर्णय लिया कि भारत के माननीय एस.सी. के 3 मार्च 1986 के आदेश के आलोक में, यदि कोई देरी हो तो उसे माफ कर दिया जाए और मामले को स्वीकार करने के बाद गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए।

याचिकाकर्ता के लिए वकील एस. सी. सिब्बल और वकील के. आर. चौधरी।

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए एस.एस. निज्जर, बार-एट-लॉ।

निर्णय

मुख्य न्यायाधीश एच. एन. सेठ,

(1) लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक क्रांति कुमार चोपड़ा प्रार्थना करते हैं कि सी.डब्ल्यू.पी. में 1983 की समीक्षा याचिका संख्या 73 दाखिल करने में देरी हुई। 1979 की संख्या 738, जिसे 24 अप्रैल 1979 को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, को माफ किया जाए और रिट याचिका को स्वीकार करने के बाद, गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय लिया जाए।

(2) संक्षेप में कहा गया है, इस आवेदन को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि आवेदक, पंजाब नेशनल बैंक का एक कर्मचारी (दफ्तरी), क्लर्क के रूप में अपनी पदोन्नति न होने के संबंध में एक औद्योगिक विवाद उठाना चाहता था। भारत सरकार ने, 12 जनवरी, 1978 के आदेश के तहत, उक्त विवाद को निर्णय के लिए संदर्भित करने से इनकार कर दिया। व्यथित होकर आवेदक ने सी.डब्ल्यू.पी. दायर की। 1979 की संख्या 738, 2 मार्च, 1979 को इस न्यायालय के समक्ष, और अन्य बातों के साथ, एक प्रार्थना की गई कि सरकार द्वारा पारित 12 जनवरी, 1978 के आदेश को रद्द कर दिया जाए और क्लर्क के रूप में उनकी पदोन्नति के संबंध में एक उचित आदेश भी दिया जाए।

(3) जब याचिका 5 मार्च 1979 को इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि 1979 की सिविल रिट संख्या 630 जैसा एक समान बिंदु मामले में शामिल था और वह उसमें दावा की गई राहत भी वही थी। तदनुसार, खंडपीठ ने निर्देश दिया कि 7 मार्च, 1979 के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया जाए। कुछ स्थगनों के बाद, मामले को 6 अप्रैल, 1979 को आदेशों के लिए सूचीबद्ध किया गया, जब न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

“प्रतिवादी के विद्वान वकील ने बताया है कि 1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 630, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया था, खारिज कर दी गई है। प्रतिवादी के विद्वान वकील के अनुरोध के अनुसार अब 24 अप्रैल, 1979 को बहस के लिए आना होगा।"

24 अप्रैल, 1979 को खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया:-

“प्रस्ताव चरण में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 'सिविल रिट संख्या 630/1979 जैसा एक समान बिंदु इस मामले में शामिल है और प्रार्थना भी वही है।' अब वह सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 630/1979 खारिज कर दिया गया है, यह रिट याचिका भी खारिज कर दी गई है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।"

इसके बाद, आवेदक ने उपरोक्त आदेश (एस.एल.पी. संख्या 3423/1980) के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने 21 मार्च, 1983 के अपने आदेश द्वारा आवेदक को विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी ताकि वह समीक्षा के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके।

(4) आवेदक ने 3 मई 1983 को इस न्यायालय के समक्ष समीक्षा आवेदन संख्या 73/1983 दायर की, जिसमें प्रार्थना की गई कि 24 अप्रैल 1979 के आदेश की समीक्षा की जाए और याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए। इस आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष तीन रिट याचिकाएं दायर की थीं, अर्थात् सी.डब्ल्यू.पी. 1979 का क्रमांक 534, सी.डब्ल्यू.पी. 1979 का क्रमांक 630 एवं सी.डब्ल्यू.पी. 1979 की संख्या 738. सी.डब्ल्यू.पी. 1979 की संख्या 534 को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के तहत कार्यवाही में श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया था, जिसमें उन्होंने क्लर्क के रूप में काम करने के लिए स्थानापन्न भत्ते का दावा किया था। उक्त याचिका, प्रस्ताव का नोटिस जारी होने के बाद, 28 मार्च 1979 को खारिज कर दी गई। सी.डब्ल्यू.पी. 1979 की संख्या 630, ओवरटाइम मजदूरी के लिए आवेदक के दावे के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33

(सी) (2) के तहत दिए गए श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ के आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया था। प्रस्ताव का नोटिस जारी होने के बाद यह याचिका भी 28 मार्च 1979 को खारिज कर दी गई। जहां तक सी.डब्ल्यू.पी. 1979 की संख्या 738 (वर्तमान कार्यवाही का विषय-वस्तु) का संबंध है, आवेदक ने याचिका में दावा किया था कि वह वर्ष 1975 से क्लर्क के रूप में पदोन्नत होने का हकदार था। याचिका, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेखित है, खारिज कर दी गई थी आदेश दिनांक 24 अप्रैल 1979 (ऊपर उद्धृत)। इसके बाद आवेदक ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे 21 मार्च, 1983 के आदेश के माध्यम से उस न्यायालय ने वापस लेने की अनुमति दी, ताकि वह उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर करने में सक्षम हो सके। तदनुसार, आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर किया, जिसमें कारण बताने के अलावा उसने दावा किया कि उसे क्लर्क के रूप में पदोन्नत न करने की प्रतिवादी की कार्रवाई गलत थी, केवल अन्य कारण पैराग्राफ 15 में बताया गया है। 24 अप्रैल 1979 के आदेश की समीक्षा का दावा करने के लिए आवेदन में इस प्रकार कहा गया था:-

"वर्तमान इस माननीय न्यायालय द्वारा समीक्षा के लिए एक उपयुक्त मामला है क्योंकि पहले खारिज की गई रिट याचिकाएं स्थानापन्न भत्ते और ओवरटाइम वेतन से संबंधित थीं और वर्तमान मामले से इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।"

इस आवेदन में, आवेदक ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं किया जिनमें उसके वकील ने 6 अप्रैल, 1979 को (मोशन सुनवाई के समय) अदालत के समक्ष कहा था कि याचिका में शामिल बिंदु और उसमें की गई प्रार्थना भी वही थी। सी.डब्लू.पी. में 1979 की संख्या 630, न ही उन्होंने यह बताया कि 24 अप्रैल, 1979 को, जब याचिका खारिज कर दी गई थी, उन्होंने अदालत के समक्ष याचिका को दबाया था और यह ध्यान में लाया था कि सी.डब्ल्यू.पी. में विवाद के बिंदु 1979 की संख्या 630, वर्तमान याचिका में शामिल लोगों से काफी अलग थी और इस तथ्य को न्यायालय के ध्यान में लाए जाने के बावजूद, याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसी तरह की याचिका (1979 की संख्या 630) पहले से ही मौजूद थी बर्खास्त।

(5) इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब आवेदक ने 3 मई 1983 को न्यायालय के समक्ष समीक्षा आवेदन प्रस्तुत किया, तो कार्यालय ने एक आपत्ति दर्ज की, जिसमें उससे यह समझाने की मांग की गई कि कैसे कहा जा सकता है कि समीक्षा आवेदन सीमा के भीतर दायर किया गया है। आवेदक ने कार्यालय रिपोर्ट के नीचे निम्नलिखित समर्थन करके इसे समझाया: -

"समीक्षा याचिका दायर की गई है, - सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 21 मार्च, 1983 के तहत।"

प्रतिवादी को नोटिस के बाद, समीक्षा आवेदन जे सुरिंदर सिंह के समक्ष सुनवाई के लिए आया। प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और अन्य बातों के साथ-साथ, इस आशय की आपत्ति उठाई कि समीक्षा आवेदन खारिज किया जा सकता है क्योंकि इसे निर्धारित सीमा अवधि से परे रखा गया है। उन्होंने बताया कि जहां समीक्षा का आदेश 24 अप्रैल, 1979 को पारित किया गया था, वहीं समीक्षा आवेदन केवल 3 मई, 1983 को किया गया था, यानी लगभग चार साल के अंतराल के बाद। हालाँकि, आवेदक की ओर से यह रुख अपनाया गया कि, इन परिस्थितियों में, 21 मार्च, 1983 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के 30 दिनों के भीतर समीक्षा आवेदन दायर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जो इस मामले में 21 मार्च, 1983 को लागू किया गया था और 5 अप्रैल, 1983 को सुनाया गया था, समीक्षा आवेदन समय के भीतर दायर किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि वर्तमान मामले में समीक्षा आवेदन दाखिल करने की सीमा अवधि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की तारीख से शुरू होनी थी जिसमें आवेदक को विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक को केवल अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी, ऐसी परिस्थितियों में आवेदक के लिए उस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था और इसे प्राप्त करने में लगने वाले समय को खारिज नहीं किया जा सकता था। समीक्षा आवेदन दायर करने के लिए निर्धारित सीमा अवधि की गणना करने में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस आशय का कोई निहितार्थ या निर्देश नहीं पढ़ा कि समीक्षा आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए, भले ही उस पर समय की रोक हो। परिणाम में, विद्वान न्यायाधीश ने माना कि चूंकि आवेदक ने

समीक्षा आवेदन दाखिल करने में हुई देरी की माफी के लिए कोई आवेदन नहीं किया है, इसलिए उसे समय से बाधित मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(6) हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल सीमा के आधार पर समीक्षा आवेदन को खारिज करके खुद को संतुष्ट नहीं किया। उन्होंने इस सवाल के गुण-दोष पर भी गौर किया कि क्या 24 अप्रैल, 1979 के आदेश की समीक्षा के लिए कोई मामला बनाया गया था या नहीं, और माना कि 24 अप्रैल, 1979 का आदेश, रिट याचिका को खारिज करने वाली परिस्थितियों में था। , बिल्कुल सही है और इसकी समीक्षा करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि भले ही समीक्षा आवेदन को सीमा के भीतर दायर किया गया माना जाता है, फिर भी वह योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, विद्वान न्यायाधीश (सुरिंदर सिंह, जे.) ने 23 मई, 1984 के अपने आदेश के तहत आवेदक द्वारा दायर समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया।

(7) व्यथित होकर, आवेदक ने एक बार फिर इस न्यायालय के 23 मई 1984 के आदेश (एसएलपी संख्या 10142/1984) के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक बार फिर, जब विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। एक पक्षीय आदेश के लिए आए, आवेदक ने इसे वापस लेने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 मार्च, 1986 को निम्नलिखित आदेश दिया:-

"विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाती है, जिससे याचिकाकर्ता को देरी की माफ़ी के लिए एक आवेदन दायर करने के उद्देश्य से फिर से उच्च न्यायालय में जाने की छूट मिल सके, यदि सलाह दी जाती है कि किस आवेदन पर उच्च न्यायालय कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर विचार करेगा।"

इसके बाद, आवेदक ने 3 मई, 1984 को समीक्षा आवेदन पेश करने में हुई देरी की माफी के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह के 23 मई, 1983 के आदेश के अनुसार इसका निपटारा कर दिया गया है।

(8) इस सवाल से निपटने से पहले कि क्या आवेदक ने 3 मई 1983 को समीक्षा आवेदन (संख्या 73 का 1983) प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने का मामला बनाया है, आदेश के निहितार्थों को स्पष्ट रूप से समझना सुविधाजनक होगा। सुप्रीम कोर्ट की दिनांक 3 मार्च, 1986।

(9) आवेदक के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप, सुरिंदर सिंह, जे द्वारा 23 मई 1984 को पारित आदेश रद्द कर दिया गया है और आवेदक का आवेदन न्यायालय के 24 अप्रैल के आदेश की समीक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। 1979, जिसके द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी गई थी, लंबित हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक को उक्त आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति दी है और उच्च न्यायालय को उस आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्पष्ट निहितार्थ यह है कि यदि उच्च न्यायालय समीक्षा आवेदन पेश करने में हुई देरी को माफ करने के लिए आवेदक के स्पष्टीकरण से संतुष्ट है, तो उसे इसे माफ कर देना चाहिए और उसके बाद इस बात पर विचार करना चाहिए कि अप्रैल के आदेश की समीक्षा के लिए कोई मामला है या नहीं। 24, 1979, आवेदक द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

(10) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इस न्यायालय के 23 मई, 1984 के आदेश से व्यथित होकर, आवेदक ने उस आदेश (एसएलपी संख्या 10142/1984) के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उक्त अवकाश याचिका सर्वोच्च

न्यायालय के समक्ष एक पक्षीय आदेश के लिए आई, आवेदक ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी, ताकि वह एक बार फिर उच्च न्यायालय में आवेदन दायर कर समीक्षा प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने की प्रार्थना कर सके। आवेदन अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह समय से बाधित था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। 23 मई, 1984 के इस न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति मांगने वाले आवेदन को वापस लेने से संभवतः उक्त आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब केवल यह है कि आवेदक ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग नहीं की है और वह इस उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। यह नहीं माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक को हस्तक्षेप के लिए अपना अनुरोध वापस लेने की अनुमति देते हुए वास्तव में मामले में हस्तक्षेप किया था और उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसके खिलाफ अपील की जानी थी, और वह भी प्रभावित पक्षों को सुने बिना। "विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाती है, साथ ही याचिकाकर्ता को देरी को माफ करने के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय में फिर से जाने की स्वतंत्रता दी जाती है, यदि सलाह दी गई हो..." स्पष्ट रूप से इंगित करता है सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक को समीक्षा आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने के लिए कोई आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं बताई। इसने यह तय करना उन पर छोड़ दिया कि क्या वह सुप्रीम कोर्ट के अपने अनुरोध या हस्तक्षेप को वापस लेने के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह का आवेदन पेश करेंगे या नहीं। संदर्भ में, आदेश में आगे की दिशा क्या है '..... किस आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा,' का अर्थ यह है कि यदि आवेदक 3 मई, 1983 को समीक्षा आवेदन (संख्या 78 का 1983) प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन करते समय, उच्च न्यायालय पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के गुणों पर विचार करते हुए कानून के अनुसार निर्णय लेगा।

(11) हमारी राय में, इस मामले में हमारे विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है:-

"क्या, जब तक न्यायालय का 23 मई, 1984 का आदेश समीक्षा "आवेदन हो" को खारिज कर देता है। 1983 का 73 (24 अप्रैल 1979 के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाला आवेदन), कायम है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है, क्या इस स्तर पर, इस न्यायालय के लिए आवेदन को माफ करने के लिए कोई आदेश पारित करना खुला है उसे प्रस्तुत करने में देरी हुई?"

निःसंदेह, दूसरा प्रश्न कि क्या आवेदक ने समीक्षा आवेदन प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने का मामला बनाया है, तभी उठेगा जब मुख्य प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होगा।

(12) जैसा कि पहले ही कहा गया है, 1983 की समीक्षा आवेदन संख्या 73 को इस न्यायालय ने 23 मई 1984 को दो कारणों से खारिज कर दिया था:

(1)आवेदन समय से बाधित था और

(2) गुण-दोष के आधार पर, 24 अप्रैल, 1979 के आदेश की समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। यदि उक्त आवेदन, प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के अभाव में, केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह समय से बाधित था, ऐसे मामले में, आवेदक के लिए कुछ व्यवहार्यता के साथ, यह आग्रह करना संभव हो सकता था कि जैसा कि न्यायालय ने किया था, उचित स्पष्टीकरण के अभाव में इस आधार पर समीक्षा आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसमें देरी हुई थी, अब भी यह उसी पर विचार कर सकता है यदि इसे अब पेश की जा रही देरी के लिए स्पष्टीकरण उपयुक्त लगता है। लेकिन फिर, वर्तमान जैसे मामले में, जहां समीक्षा आवेदन को न केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि यह समय से बाधित है, बल्कि इस आधार पर भी खारिज कर दिया गया है कि योग्यता के आधार पर भी, समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, केवल विचार मात्र है इसे प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने के अनुरोध से, हमारी राय में, कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। भले ही आवेदक द्वारा समीक्षा आवेदन प्रस्तुत करने में देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार कर

लिया जाए, फिर भी इस न्यायालय के लिए उसके द्वारा पहले निकाले गए निष्कर्ष को खारिज करना संभव नहीं होगा, अर्थात् गुण-दोष के आधार पर आदेश की समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। बाहर कर दिया। यह न्यायालय 23 मई 1984 के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इसके विपरीत रुख नहीं अपना सकता है क्योंकि उस आदेश के संबंध में उसके पास न तो अपीलीय और न ही पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है, जो कि, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, अभी भी कायम है। वर्तमान आवेदन निश्चित रूप से 23 मई, 1984 के आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन नहीं है, और यदि ऐसा था भी, तो यह बहुत संदिग्ध है कि क्या यह रखरखाव योग्य होगा। इन परिस्थितियों में, यह विचार करना व्यर्थ होगा कि क्या आवेदक समीक्षा आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने का मामला बनाने में सफल हुआ है।

(13) परिणाम में, हमारी राय है कि जब तक 23 मई 1984 का आदेश कायम है, 1983 की समीक्षा आवेदन संख्या 73 प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने के आवेदक के अनुरोध पर विचार करना व्यर्थ होगा। इसलिए, यह आवेदन विफल हो जाता है और अस्वीकार कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh